

राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया विपक्ष ने

मुद्दा था, संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र, जो सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए आहूत किया है

रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अप्रैल। राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की एक बैठक में, तृणमूल कांग्रेस की प्रतिनिधि और सांसद सागरिका घोष ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सभी सांसद संसद में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि केवल 5 से 7 सांसद ही मौजूद रह सकें।

इस पर आहत राहुल गांधी ने कहा कि यदि विपक्षी दलों के सभी सांसद नहीं आएंगे, तो यह संसद में भाजपा की मदद करने के बराबर होगा।

राहुल गांधी का समर्थन करते हुए, द्रमुक के टी.आर. बालू ने कहा कि तमिलनाडु में भी चुनाव हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी के सभी सांसद संसद में बहस में हिस्सा लेने और अपनी आवाज उठाने के लिए उपस्थित

- विपक्ष की बैठक में राहुल ने पुरजोर तरीके से कहा कि विपक्ष के सभी सांसद उपस्थित होने चाहिए, संसद में जब सरकार विधेयक को पारित करने के बहाने, संसदीय सीटों का परिशीलन करना चाहती है।
- तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा, तृणमूल के सभी सांसद उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प.बंगाल में चुनाव चल रहे होंगे।
- डी.एम.के. सांसद बालू, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में पार्टी के नेता संजय सिंह, शिव सेना के नेता उद्धव ठाकरे, जो विपक्ष की बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए थे, एक स्वर में राहुल गांधी की बात का पुरजोर समर्थन किया और तृणमूल के प्रतिनिधि पर पुरा दबाव बनाया कि तृणमूल के सभी सांसद, विशेष सत्र में उपस्थित होने चाहिए। क्योंकि भाजपा को घेरना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर भाजपा की मनमानी बेरोकटोक चलती रही तो प्रजातंत्र ही खतरे में आ जाएगा और चुनाव भी बेमामने हो जायेंगे।
- राहुल के नेतृत्व को शायद पहले विपक्ष का पूर्ण समर्थन कभी नहीं मिला है।

रहेंगे। "आप" के सांसद और राज्यसभा नेता संजय सिंह ने इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सांसद उपस्थित हों।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा चुनावों से बड़ा है और अगर स्थिति ऐसी ही रही,

तो लोकतंत्र ही अर्थहीन हो जाएगा और चुनाव बेकार हो जाएंगे।

शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, जो बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे, ने कहा कि वे ममता बनर्जी से बात करेंगे और उनकी पार्टी के सभी सांसदों की संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने की

आवश्यकता पर जोर देंगे।

अन्य उपस्थित लोगों ने भी यही भावना व्यक्त की और सभी ने उम्मीद जताई कि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सभी सांसद इस मुद्दे पर भाजपा को परास्त करने के लिए संसद में उपस्थित होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आरएएस हनुमाना राम को जमानत नहीं दी

जयपुर, 15 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर दो उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा देने वाले निलंबित आरएएस हनुमाना राम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीर्घाकर दत्ता और जस्टिस

■ अदालत ने कहा कि आरएएस होते हुए भी डमी अभ्यर्थी बनने वाले को जमानत नहीं मिल सकती।

सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश आरोपी हनुमाना राम को जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पर तीन व्यक्तियों के लिए डमी अभ्यर्थी बनने का आरोप है। यह एक घटना नहीं है, बल्कि आरोपी के निरंतर आचरण को दर्शाती है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालत ने सुबोध अग्रवाल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

जयपुर, 15 अप्रैल। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

एसीबी की ओर से रिमांड अर्थात् पूरी होने के बाद बुधवार को सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया। एसीबी की ओर से कहा गया कि अभी तक आरोपी से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में उसकी रिमांड अर्थात् दो दिन और बढ़ाया जाए। इसका विरोध

■ जलजीवन मिशन घोटाले के आरोपी अग्रवाल ने खतरों की आशंका जताते हुए अलग सेल में रखने की प्रार्थना की।

करते हुए सुबोध अग्रवाल के वकील ने कहा कि उन्होंने एसीबी के सवालों का जवाब दे दिया है। ऐसे में उन्हें जेल भेजा जाए। इसके साथ ही, उन्होंने जेल में खतरा बताकर अन्य कैदियों से अलग सेल में रहने की गुहार की। सुनवाई के दौरान सुबोध अग्रवाल ने कहा कि एसीबी अधिकारी मीडिया को कह रहे हैं कि उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, बताइए उन्होंने किन सवालों के जवाब नहीं दिए। गौरतलब है कि एसीबी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक और भेजे

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ये दस हजार सैनिक गल्फ क्षेत्र में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों को जाँइन करेंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान में युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही, पेंटागन की योजना के अनुसार, अस्थायी युद्धविराम के 22 अप्रैल को समाप्त होने से ठीक पहले, मध्य पूर्व में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं। संकेत स्पष्ट है: जहाँ ट्रम्प युद्ध के जल्द खत्म होने की बात कर रहे हैं, वहीं वॉशिंगटन इस संभावना के लिए तैयारी कर रहा है कि संघर्ष और लंबा और गंभीर हो सकता है।

ट्रम्प अपने युद्ध संबंधी बयानों में विरोधाभासों को लेकर लगातार विवादित रहे हैं। उन्होंने हाल ही में फॉक्स न्यूज को कहा, "मुझे लगता है कि यह (संघर्ष) बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा।" एक अन्य बयान में उन्होंने कहा, "दुनिया अगले दो दिनों में तैयारी से होते घटनाक्रम की गवाह बनेगी।" "वॉशिंगटन पोस्ट" की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 6,000 सैनिक एयरक्राफ्ट

विशेषज्ञों के अनुसार, एक तरफ तो अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, दूसरी तरफ अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, इससे ऐसा लगता है कि सीज़फायर, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है, के बाद संघर्ष और लंबा खिंच सकता है।

■ ट्रंप, ईरान युद्ध के बारे में परस्पर विरोधाभासी बयानबाजी करते रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा, मुझे लगता है, यह (युद्ध) जल्दी ही खत्म हो जाएगा, पर, अगले बयान में उन्होंने कहा, विश्व अगले दो दिनों में भारी सैन्य बल तैनाती देखेगा।

■ वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, 6,000 सैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश व उसके साथ के जहाजों से लिए गए हैं तथा 4,200 सैनिक बॉक्सर एम्फीबियस रैंडी ग्रुप व इलैन्वथ मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट से लिए गए हैं।

कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश और उसके एस्कॉर्ट जहाजों पर हैं, जबकि अन्य 4,200 सैनिक बॉक्सर एम्फीबियस रेंडी ग्रुप और 11 वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट से हैं। ये अतिरिक्त सैनिक लगभग 50,000 अमेरिकी कर्मियों के साथ शामिल होंगे, जो पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं।

मध्य पूर्वी जल क्षेत्रों में तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं।

इस समय, अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रहा है, तथा ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत कई जहाजों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की ज़ैड प्लस सुरक्षा वापस ली

राघव की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिसकर्मियों को तुरंत हैड क्वार्टर रिपोर्ट करने को कहा गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता पद से हटाए जाने के कुछ ही दिन बाद, पंजाब सरकार ने आज सांसद को दी गई ज़ैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली।

37 वर्षीय चड्ढा की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को तुरंत मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

विश्व बैंक ने राजस्थान को 2,000 करोड़ रूपए दिए

जयपुर, 15 अप्रैल। विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ एजीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने राजस्थान में राज्य राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा सुधार के लिए 225 मिलियन डॉलर (लगभग 2 हजार करोड़ रुपये) से अधिक की

■ यह राशि राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के तहत 800 किमी सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के लिए दी गई है।

राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। विश्व बैंक के अनुसार, इस परियोजना से औद्योगिक, खनन, पर्यटन और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी का लाभ भी मिलेगा।

यह परियोजना राजस्थान और राजमार्ग प्राथिकरण को आधुनिक और सेवा केन्द्रित बनाने में मददगार साबित होगी। इससे प्राथिकरण प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर के चयनित राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव करेगा। साथ ही, राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा। इस स्वीकृत प्रोजेक्ट से भारत में पहली बार स्टैप- (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ साफ जाहिर है कि आप नेतृत्व और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप नेतृत्व का आरोप है कि राघव संसद में प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रभावी तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और अपने व्यक्तिगत प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि राघव ने इन आरोपों का खंडन किया है।

■ इसी वजह से पहले उन्हें राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटाया और अब ज़ैड प्लस सुरक्षा भी छीनी गई।

यह कार्यवाही आप और उसके पंजाब सांसद के बीच तेजी से बढ़ते और कटु होते मतभेदों के बीच की गई है। आप ने चड्ढा पर आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार के खिलाफ संसद में अपनी आवाज उठाने से बचते रहे और इसके

बजाय "साँपट पीआर" में लगे रहे। इसी कारण पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया। चड्ढा ने पार्टी के आरोपों को "बुद्ध" करार देते हुए कहा कि वे संसद में लोगों के मुद्दे उठाने जाते हैं, हंगामा करने के लिए नहीं।

अमेरिका के ब्लॉकेड के प्रत्युत्तर में ईरान ने भी "काउन्टर ब्लॉकेड" की धमकी दी

अगर ईरान अपनी धमकी के अनुरूप "रेड सी" से ब्लॉक कर देता है, इस पूरे इलाके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकदम ठप्प हो जाएगा

-अंजन राँय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अप्रैल। अमेरिकी सरकार द्वारा होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी पर गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए, ईरान ने पश्चिम में लाल सागर से लेकर पूर्व में ओमान की खाड़ी तक विस्तृत जल क्षेत्र में जवाबी अवरोध की धमकी दी है। यदि यह प्रभावी ढंग से किया गया, तो इससे पूरे क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है, जिनमें यूरोप-एशिया मार्ग के लिए स्वेज नहर का उपयोग करने वाले जहाज भी शामिल हैं।

थलग करने के प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट संकेत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ दो सप्ताह की युद्धविराम अवधि बढ़ाने और होर्मुज़ स्ट्रेट की नौवहन सुविधा पर गतिरोध को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से वार्ता फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने एकतरफा तौर पर ईरान के साथ संवाद फिर से शुरू करने की संभावनाओं की घोषणा की है, ताकि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वार्ता शुरू की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान का परमाणु मुद्दे पर प्रस्ताव और होर्मुज़ स्ट्रेट को पुनः खोलने का प्रस्ताव, अन्य कारणों के साथ, वार्ता को रोक रहा था। डॉनल्ड ट्रम्प जोर दे रहे हैं कि वार्ता इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होनी

- चीन व रूस भी इस ब्लॉकेड प्रकरण में ईरान के साथ हैं तथा अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है।
- हताशा होकर, अमेरिका ईरान से दोबारा वार्ता शुरू करना चाहता है, जिससे दो सप्ताह की "सीज़फायर" की अवधि कुछ और समय तक बढ़ाई जा सके।
- ट्रंप ने अपने आप एक तरफा घोषणा कर दी है कि वार्ता शुरू हो रही है।
- ट्रंप इस्लामाबाद में वार्ता करना चाहते हैं, पर, दूसरा पक्ष यूरोप में किसी सैन्ट्रल स्थान पर वार्ता आयोजित करना चाहता है।

चाहिए, जबकि कुछ अन्य पक्ष सुझाव दे रहे हैं कि इसे ऐसे स्थान पर किया जाए जो ज्यादा केन्द्रीय क्षेत्र, जैसे कि यूरोप के किसी स्थान, में आयोजित किया

जाना चाहिए। स्थान परिवर्तन से संभवतः अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व की संभावना बन सकती है। विडंबना यह है कि सबसे बड़ी

अडचन है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो, केवल उन शर्तों को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो जेसीपीओए समझौते के तहत पहले ही प्राप्त हो चुकी थीं। जेसीपीओए समझौता, जो प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ था, डॉनल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद ईरान ने जेसीपीओए समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं से बाहर निकलते हुए एक मजबूत परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, जिससे परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने की संभावना बढ़ गई। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता कई मुद्दों पर अटक हुई थी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम भी शामिल था। वार्ता विफल होने के बाद,

के लिए आवेदन करते हैं, तो इस रोक का उन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई प्रतिकूल

निष्कर्ष निकालेगा। पीठ ने पवन खेड़ा और अन्य प्रतिवादिियों को नोटिस भी जारी किया है, और असम सरकार की हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उनके जवाब मांगे हैं।

सीबीएसई के कक्षा दस के नतीजे घोषित

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को कक्षा 10 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल 93.70 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

■ छात्रों का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा 94.99 प्रतिशत छात्रों तथा 92.69 प्रतिशत छात्र पास हुए।

हुए, जो पिछले वर्ष के 93.66 प्रतिशत की तुलना में 0.04 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। बोर्ड के अनुसार, इस वर्ष 24,83,479 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 24,71,777 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 23,16,008 छात्र-छात्राएं सफल घोषित किए गए। परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक किया गया था। क्षेत्रवार प्रदर्शन में, त्रिवेन्द्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र 99.79 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)